Modernisation of State Police Forces as well as by releasing funds on the basis of recommendations of the Finance Commission. Improvement in the police functioning is a continuous process and the Central Government is committed to ensure that the State Governments get all assistance to improve the policing in the country.

विदेशों से प्राप्त धन का प्रयोग आदिवासियों में राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए किया जाना

25. **श्री जनार्दन यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ गैर-सरकारी संगठन अब विदेशी धन के जरिए आदिवासियों में राजनीतिक गतिविधियां चला रहे हैं;

(ख) ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन संगठनों की गतिविधियों से आदिवासियों के हितों की रक्षा हो रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) हाल ही में इस प्रकार का कोई विशिष्ट दृष्टांत सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

पुलिस बलों में महिलाओं को भर्ती किया जाना

26. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पुलिस सेवाओं के सभी स्कन्धों में भर्ती की गई महिला पुलिस बलों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि महिला पुलिस बल की संख्या देश में महिलाओं के प्रति किए गए अपराध की दर और पात्र महिलाओं की संख्या की तुलना में बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पुलिस सेवा में अधिक महिलाओं की भर्ती करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी मौजूदा स्थिति संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य सरकार के विषय हैं। अतः निश्चित रूप से यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अपने पुलिस बल के गठन के बारे में निर्णय लें और अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार अपने पुलिस बल में और अधिक महिलाएं भर्ती करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं। अपने पुलिस बल के प्रयोग को नियंत्रित करने में राज्य सरकारें पूर्ण सक्षम हैं।

महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या तथा महिला पुलिस बल की संख्या के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, चूंकि महिलाओं के प्रति अपराध सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक कारणों सहित विविध कारणों से होते हैं।

ULFA Training Camps in Myanmar

27. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that training facilities are being provided to the ULFA cadres in camps manned by two prominent factions in Myanmar—the Karen National Union (KNU) and the Clin National Army (CNA) and the NOSONK-K is the crucial link between these factions, if so, the details of the activities being carried out there; and

(b) what remedial steps at the bilateral level talks were taken during recent visit of the Home Secretary to Myanmar and what has been the outcome as on date?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Reports indicate that there are camps in Myanmar which are being used by North East insurgent groups for safe havens, sanctuary and training purposes.

(b) Both sides stressed on the coninued need for taking actions against insurgents and other negative elements operating from their soil against the other. Both sides reitereated that they do not allow their territories to be used for activities against each other. The Myanmar side

has agreed to intensify the existing contacts and communication links at the local level to facilitate action against insurgent arms traffickers and other negative elements.

राज्यों में मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाना

28. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य स्तर पर मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सहित किसी राज्य ने ऐसा कोई आयोग स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इनके अधिकारों का क्षेत्र किस सीमा तक बढ़ाया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) अधिनियम की धारा 21 से 29 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने के लिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में आधिकारिक प्रावधान हैं। राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की सलाह दी गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित कर लिए हैं। गुजरात की राज्य सरकार ने अपने राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित नहीं किया है।

(घ) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 की उप-धारा (5) के उपबन्धों के अनुसार, किसी राज्य आयोग का क्षेत्राधिकार संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II और सूची-III में बताई गई किसी भी प्रविष्ट से संबद्ध मामलों तक ही सीमित है।

ULFA Ultras activities in West Bengal

29. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-items appreared in the 'Hindustan Times' New Delhi dated the 11th April, 1998 under the caption "Calcutta emerges ULFA hide out for Arms Purchase";

(b) if so, what is Government's reaction thereto; and

(c) the action being taken by Government of prevent the ultras taking shelter in West Bengal?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Madam.

(b) and (c) The Central Government remains in close contact with the State Government of West Bengal to ensure that insurgent groups do not use the State for anti-national activities. State Police and intelligence agencies have been instructed to, remain vigilant in this regard.

पुलिस शिकायत प्राधिकरण

30. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध जन-शिकायतों की ठोस सुनवायी से संबंधित "पुलिस शिकायत प्राधिकरण" का मामला लम्बे समय से सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या उक्त योजना को सैद्धान्तिक सहमति दिसम्बर, 1996 में दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में हुए विलम्ब का क्या कारण है और प्राधिकरण बनाने के मामले पर सरकार का अन्तिम निर्णय क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में 2 अगस्त, 1996 को राज्य सभा में वक्तव्य देते हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली पुलिस के सदस्यों की लापरवाहियों और ज्यादतियों के खिलाफ जन शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से एक स्वतंत्र पुलिस शिकायत प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित प्राधिकरण के ढांचे, स्वरूप, कार्यक्षेत्र इत्यादि की संकल्पना के लिए कदम उठाए गए है। यह एक समय लगने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अर्न्तग्रस्त कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों पर बार-बार अन्तर मंत्रालयीय परामर्श करना पड़ता है। इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वर्तमान लोक